

ग्रामीण जल जीवन मिशन में मध्यप्रदेश बना उदाहरण

भोपाल ,एजेंसी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्य सत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रमुख सचिव श्री पी. नरहरि ने जल जीवन मिशन में मध्यप्रदेश द्वारा अपनाए गए डेटा-संचालित सुधारों पर केंद्रित प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि राज्य में योजनाओं के सतत संचालन के लिए तकनीकी दक्षता, ग्रामीण समुदायों की भागीदारी और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। प्रमुख सचिव श्री नरहरि ने बताया किप्रभावी बनाने के लिए राज्य ने संपर्क-समस्या-समाधान की स्पष्ट प्रणाली विकसित की है, जिससे सेवा में निरंतरता बनी रहती है। कार्यशाला में मध्यप्रदेश जल निगम के प्रबंध संचालक श्री केवीएस चौधरी ने राज्य के तकनीकी दृष्टिकोण और फ़ोल्ड लेवल अनुभव साझा किए।

कार्यशाला में मध्यप्रदेश के प्रयासों की अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा सराहना की गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संचालन और अनुरक्षण नीति को मजबूत करने के लिए राज्यों के बीच सहयोग और नवाचार साझा करना समय की मांग है।

मंत्री सुश्री भूरिया महिला बाल विकास” पर पश्चिमी राज्यों की जोनल मीट में होंगी शामिल

भोपाल ,एजेंसी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुजरात के केवड़िया में आयोजित होने जा रही पश्चिमी क्षेत्रीय राज्यों की जोनल मीट में मध्यप्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बैठक केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बाल विकास योजनाओं के बेहतर समन्वयन और क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श, केंद्र एवं राज्यों के बीच नीतिगत सहयोग और अनुभवों का आदान-प्रदान, पोषण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा और क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के लिए साझा रणनीति तैयार करना है। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, मध्यप्रदेश, दमन एवं दीव तथा दारुवा एवं नगर हवेली के महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया बैठक में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाइली बहना योजना, मोटी आई, सक्षम आंगनवाड़ी अभियान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया, एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएं और पोषण ट्रेकिंग जैसे नवाचारों की जानकारी साझा करेंगी। बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये राज्य में किए जा रहे प्रभावशाली प्रयासों की प्रस्तुति भी देंगी।

शुद्ध जल का करें उपयोग, जलजनित रोगों से स्वयं को रखें सुरक्षित

भोपाल ,एजेंसी। वर्षा ऋतु में होने वाली जलजनित बीमारियों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और दूषित जल से होने वाले रोगों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियाँ अपनाएँ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुद्ध जल का उपयोग करने एवं जलजनित रोगों से सुरक्षा के लिए सलाह दी गई है। दूषित पानी के सेवन से उल्टी-दस्त, पैंचिश, हैजा, पीलिया और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि रोगों से बचने के लिए सावधानियाँ और सुरक्षा उपाय अपनाकर स्वयं एवं परिवार को सुरक्षित करें। स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी में कहा है कि खानपान के लिए सदैव स्वच्छ एवं सुरक्षित उबला अथवा फिल्टर जल का ही प्रयोग करें। यदि पानी की शुद्धता संदिग्ध हो, तो उसे पहले उबालें, साफ कपड़े से छानें अथवा क्लोरीन की गोली डालें और कम से कम एक घंटे के बाद उसका सेवन करें।

खिलाड़ियों के वैश्विक विकास के लिए शुरू होगा ‘एक्सचेंज प्रोग्राम’- मंत्री सारंग

भोपाल ,एजेंसी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्यप्रदेश को हॉकी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए ह्रसंभव प्रयास किए जायें। इसी कड़ी में उन्होंने ‘प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम’ प्रारंभ करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी देश एवं विदेश की प्रतिष्ठित अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों के कौशल में उल्लेखनीय सुधार होगा और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। मंत्री श्री सारंग शुक्रवार को तात्या टोपे



खेल स्टेडियम में मध्यप्रदेश पुरुष हॉकी खेल अकादमी की समीक्षा कर रहे थे।

मंत्री श्री सारंग ने अकादमी में प्रशिक्षण, खिलाड़ियों की प्रगति,

प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विदेशी विशेषज्ञ कोच को भी आमंत्रित किया जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अकादमी के 8 खिलाड़ी ‘इंडियन कोर ग्रुप’ में शामिल हैं, और अब यह लक्ष्य बढ़ाकर 16 खिलाड़ियों तक पहुंचाने की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में पुरुष हॉकी अकादमी का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा है इस वर्ष की रणनीति को आधार बनाकर आगामी प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया को संचालित किया जाए। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि खिलाड़ियों के लिये एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की जाये।

आधारभूत सुविधाओं एवं अकादमी संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि अकादमी में

भोपाल ,एजेंसी। राष्ट्रीय आयुष मिशन की नीतिगत दस्तावेज के लिए अंतर्राज्यीय बैठक शुक्रवार को मध्यप्रदेश के नेतृत्व में भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संबंधित राज्य के आयुष विभाग के उच्च अधिकारी सम्मिलित हुए हैं। आयुष चिकित्सा को मुख्य धारा में लाकर आमजन को उच्च स्तरीय आयुष चिकित्सा प्रदान करना तथा आयुष विभाग की अधोसंरचना एवं उच्च गुणवत्तायुक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही 2047 के विकसित भारत के संकल्प में आयुष का



महत्पूर्ण योगदान सुनिश्चित करना भी बैठक का उद्देश्य रहा।

आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण के उपविषयों का चयन किया। संगठनात्मक संरचना की समीक्षा मानव

संसाधन सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण के नोडल राज्य मध्यप्रदेश एवं सिक्किम हैं। वर्किंग ग्रुप के अन्य सदस्य राज्य बिहार, दिल्ली, गोवा एवं नागालैण्ड हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में अप्रैल में हुई बैठक में नीति

आयोग द्वारा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में विचार विमर्श के लिए आगामी 6 शिखर सम्मेलन के 6 विषय का चयन किया गया है। चयनित विषयों में से एक विषय के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण का चयन किया गया है वर्किंग ग्रुप मीटिंग में मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय आयुष मिशन के राज्य प्रमुख/प्रबंधक के साथ केंद्रीय आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डॉ ए. रघु, प्रदेश की आयुष आयुक्त आर उमा आयुष डायरेक्टर डॉ योगिता मुंजाल एवं अन्य राज्य से आए प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में बनेंगे 2 सामुदायिक भवन-मंत्री श्री पटेल

भोपाल ,एजेंसी। मध्यप्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 5 हजार से ज्यादा है उन पंचायतों में दो सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 10 से 12 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर-क्लस्टर वाली ग्राम पंचायत में उप यंत्री का कार्यालय बनाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को बालाघाट जनपद पंचायत के ग्राम भरखेली में 64 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सर्व-सुविधायुक्त ग्राम पंचायत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते यह बात हुए कही। उन्होंने ग्राम पंचायत भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं समाज सेविका माता सावित्री

बाई फुले की प्रतिमा का अनावरण किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भरखेली ग्राम पंचायत भवन लोकार्पण का कार्यक्रम यादगार दिन है। देश के विकास की रीढ़ माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी एवं महान समाजसेवी सावित्री बाई फुले की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर सौभाग्य की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी के प्रयासों से देश के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। उनके द्वारा प्रारंभ की गई यह योजना आज भी फलीभूत हो रही है। समाजसेविका सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो काम किया है उसे

भुलाया नहीं जा सकता है। आने वाले समय में प्रदेश में बिना भवन की कोई भी ग्राम पंचायत नहीं रहेगी। राज्य में चरण बद्ध रूप से ग्राम पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं और उनके साथ ही सामुदायिक भवन भी बना रहे हैं। जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 05 हजार से अधिक है वहां पर दो सामुदायिक भवन बनाये जाएंगे। भरखेली को भी इसका लाभ मिलेगा। मंत्री श्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान में बालाघाट जिले के प्रदेश में तृतीय स्थान पर आने के लिए सराहना करते हुए कहा कि बालाघाट जिले ने इस अभियान में अच्छा कार्य किया है। उन्होंने प्रशासन एवं जन-प्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15

जुलाई से 15 अगस्त तक सरकारी भूमि पर पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में पौधे लगाने के साथ ही उनके जीवित रहने की गारंटी भी ली जाएगी। पौधे उन्हीं स्थान पर लगाए जाएंगे जहां उनकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था होगी और गर्मियों के दिनों में पानी की व्यवस्था होगी। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक एक बगिया मां के नाम अभियान चलाया जाएगा और इसमें ऐसे महिला समूह जिनके पास 01 एकड़ भूमि उपलब्ध है उस पर फलों के पौधे लगवाए जाएंगे। महिला समूह को पहले वर्ष 02 लाख रुपए, दूसरे वर्ष 52 हजार रुपए एवं तीसरे वर्ष 48 हजार रुपए की राशि उनके कार्य की प्रगति पर दी जाएगी।

प्रदेश के दो मुक्केबाज खिलाड़ियों का - 22 नेशनल कैप के लिए चयन

भोपाल ,एजेंसी। मध्यप्रदेश के दो उभरते मुक्केबाजों मलिका 48 किग्रा वर्ग एवं अमन 90 किग्रा वर्ग का चयन अंडर-22 राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। यह प्रशिक्षण शिविर 12 से 30 जुलाई तक आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूट पुणे में आयोजित होगा। मध्यप्रदेश के इन होनहार खिलाड़ियों के चयन पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रशिक्षण शिविर न केवल उन्हें तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाएगा, बल्कि आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

की बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों खिलाड़ी आने वाले समय में देश के लिए पदक जीतेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पुणे में आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर न केवल उन्हें तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाएगा, बल्कि आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

के लिए पदक जीतेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पुणे में आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर न केवल उन्हें तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाएगा, बल्कि आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

कार्य में उदासीनता बरतने वाले चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर हुई कार्यवाही

भोपाल ,एजेंसी। शहरी क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में कार्य के दौरान लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सीएमएचओ भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने कार्यवाही करते हुए वेतन कटौती सहित कारण बताओं नोटिस जारी किया है। 9 जुलाई को आयोजित एक्सपर्टडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक नटखट चौराहा के चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुमित त्यागी को कारण बताओं नोटिस जारी कर 7 दिन का वेतन काटा गया है। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना और हितग्राहियों को स्वास्थ्य लाभ से वंचित करने के कारण उनके विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक दशमेश नगर के चिकित्सा अधिकारी डॉ.आयुष्मान सिंह एवं नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती दुर्गाक्षरी पटैया को ओपीडी के समय संस्था से अनुपस्थित मिलने पर कारण बताओं नोटिस जारी कर 7 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए हैं।

मुयमंन्त्री डॉ. यादव 13 से 19 तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर



हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 13 से 19 जुलाई को दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। यह दौरा मध्यप्रदेश की वैश्विक निवेश रणनीति में महत्वपूर्ण कदम होगा। दुबई में मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेश को लेकर इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख बैठक प्रस्तावित है, जहां मध्यप्रदेश की औद्योगिक तैयारियों और निवेश नीति को लेकर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दुबई में कार्यरत लुलु इंटरनेशनल ग्रुप, लैंडमार्क ग्रुप और नखोल ग्रुप जैसे अंतर्राष्ट्रीय रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता करेंगे, जिनमें प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस, रिटेल चेन और निवेश संबंधी अन्य सहयोग पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दुबई के बाद 16 से 19 जुलाई तक स्पेन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव बार्सिलोना में स्पेन की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों और ग्रीन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण संवाद करेंगे। बार्सिलोना में होने वाली बैठकों में टेक्सटाइल, गारमेंट और डिजाइन सेक्टर की अग्रणी कंपनियों से भी चर्चा की जाएगी, जिससे मध्यप्रदेश में पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल ओडीओपी और वर्धमान सहित टेक्सटाइल क्लस्टर को और गति दी जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की स्पेन यात्रा का एक बड़ा फोकस पर्यटन और हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी रहेगा।

गैस पाइप लाइन फटने से लगी भीषण आग

दहशत में लोग, इंडियन ऑयल ने पाया काबू

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा के समान थाने के संजय नगर मोड़ स्थित एक विद्यालय के पास गैस पाइप लाइन फटने से भीषण आग भड़क गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की तेज लपटों को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही इंडियन ऑयल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अग्निशामक गंत्रों की मदद से आग पर काबू पाया। जानकारी के



अनुसार, एक दिन पहले विद्यालय में लगभग दो फीट पानी भर गया था। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम की जैसीबी मशीन कच्ची नाली की खुदाई कर रही थी। इसी दौरान नीचे से गुजर रही गैस पाइप लाइन को जैसीबी का बकेट लग गया, जिससे मुख्य सर्विस लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे एलपीजी गैस तेजी से रिसने लगी और आग भड़क गई। आग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि ऊपर से गुजर रही बिजली की केबल भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे अफरातफरी का माहौल बन गया। इंडियन ऑयल की टीम ने तुरंत मुख्य नोजल बंद कर

दिया, लेकिन पाइप लाइन में बची गैस के कारण आग कुछ देर तक जलती रही। फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, जो मौके पर पहुंची। हादसे के चलते सड़क पर घंटों जाम रहा और एहतियात के तौर पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई ताकि कोई जनहानि न हो। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठाए, क्योंकि नाली की खुदाई के दौरान पाइप लाइन की स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया। प्रशासन और संबंधित विभागों से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है।

अमर ज्योति ने करवाया दो मातृशक्तियों का नेत्रदान



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। विंध्य क्षेत्र में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने वाली संस्था अमर ज्योति ने 11 जुलाई को नागौद और जैतवारा में दो नेत्रदान करवाए। संस्था के संयोजक मनोहर डिगवानी ने बताया कि नागौद निवासी अरविंद, अनिल और सचिन अग्रवाल की, पूजनीय माता कमलादेवी अग्रवाल तथा जैतवारा निवासी सुनील अनिल अग्रवाल की पूजनीय माता सरला अग्रवाल का 11 जुलाई को स्वर्गवास हो गया।

अमर ज्योति के बलराम गुनानी, राजकुमार सुंदरानी, वीरेंद्र अग्रवाल (नागौद) और दीप अग्रवाल की प्रेरणा से दोनों परिवारों ने अपनी माताश्री का नेत्रदान करने का निर्णय लिया। सतगुरु की तकनीकी टीम ने नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण की। संस्था के सदस्य विनोद गहलानी ने बताया कि यह संस्था का 849वां नेत्रदान है। इस पुण्य कार्य से चार नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में रोशनी आएगी, और नेत्र प्राप्त करने वाले

परिवारों को आजीवन दुआएं देंगे। संस्था के मार्गदर्शक योगेश ताम्रकार, संयोजक मनोहर डिगवानी, कमल पुरस्वानी, मनोज अरोरा, नरेंद्र चंद्र गुप्ता, पुष्पराज सिंह, हरिओम गुप्ता, मनमोहन माहेश्वरी, विभाष बनर्जी, सुधीर जैन, ललित खुराना, दिलीप सोनी, प्रदीप अरोरा, विपुल हांडा, संजय वाधवानी, अनिल मोटवानी, जेठानंद वाधवानी, घनश्याम मीधरानी, श्यामलाल गुप्ता, मनोज वलेजा, संदीप चमडिया, अनिल झुलवानी, नीलांबर झा, बसंत शर्मा, संदीप धृत, दीपक वाधवानी, रूपेश वलेचा, तरुण ठक्कर, भरत आहूजा, पंकज आहूजा, श्रीमती मंजूषा शाह, दिनेश अग्रवाल, अशोक ताम्रकार, उमेश लोहिया, डॉ. प्रकाश सिंह, ज्ञान खटवानी, मनीष टैकवानी, धीरज टंडन, बलराम गुनानी सहित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों के इस नेक निर्णय के लिए साधुवाद व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री शनिवार को लाड़ली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे 26वीं किश्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सिलेंडर उज्ज्वला की राशि भी करेंगे अंतरित

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार 12 जुलाई को ग्राम पंचायत नलवा जिला उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में जुलाई माह की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन के कालिदास अकादमी में राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन में मुख्यआ कल्याण के

विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं हितलाभ का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत एक करोड़ 27 लाख बहनों को 1503 करोड़ 14 लाख की 26वीं किश्त उनके खातों अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 56 लाख 74 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ की राशि, 30 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिलिंग की 46 करोड़ 34 लाख की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कालिदास अकादमी में राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन में मछुआ कल्याण के 152 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं मछुआओं को हितलाभ का भी वितरण करेंगे।

करेला की खेती कर मैहर जिले के किसान कमा रहे लाखों का मुनाफा

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मैहर जिले के किसान करेले की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। करेले की खेती बरमा, धतूरा, कुसेड़ी, भरौली, घुनवारा, मतवारा, हिनौता कला, बरमा, बेलहाई, नई दिल्ली, परसवाड़ा, मनौरा जैसे कई अन्य छोटे-छोटे 12 गांव के 2500 से अधिक किसान करेले की खेती करते हैं। इससे किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। पहले भी मैहर में करेले की खेती की जाती रही है, लेकिन वर्तमान में करेले की उपयोगिता को देखते हुए किसान सीजन में सिर्फ करेले की खेती को अधिक महत्त्व देते हैं।

पहले ये किसान पारंपरिक खेती करते थे। लेकिन सिंचाई के साधन नहीं होने की वजह से इन्होंने सब्जी की बड़े पैमाने में खेती करने का मन बनाया। किसानों को करेला बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ता। किसान करेले की छटाई कर बड़े-बड़े पॉलीथिन के बैग में भर कर बाजार कर रखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के किनारे होने की वजह से लोग



सीधे किसानों से संपर्क कर करेला खरीद ले जाते हैं। किसान जमीन के छोटे से टुकड़े में भी करेले की खेती करके ज्यादा लाभ कमाते हैं। अप्रैल माह से अगस्त माह के बीच 1 एकड़ जमीन पर किसान करेले की खेती कर 1 से 1.5 लाख रुपये एक सीजन में कमा लेते हैं। यही एक ऐसी खेती है जिसमें नुकसान नहीं होता। बाहरी

राज्यों से डिमांड बढ़ने की वजह से परिवार के सभी सदस्य इसी काम में लगे रहते हैं। एक बार बोनी के बाद जून, जुलाई, अगस्त तक करेले की फसल चलती है। करेले की खेती के लिए अप्रैल माह में खेत की गोड़ाई कर गाय एवं भैंस के सूखे गोबर का गिड़काव करने के बाद 2-2 फिट की दूरी पर

2 से 3 इंच का गड्ढा बनाकर बीज की बुवाई की जाती है। 15 दिन बाद पौधे निकल आते हैं। जिसकी छटाई कर पौधे के पास लकड़ी गाड़ के बेल को उसके सहारे ऊपर की ओर चढ़ा दिया जाता है। दो माह में पौधे में करेला निकलना शुरू हो जाता है। जो कि जून, जुलाई एवं अगस्त तक रहता है उसके बाद समाप्त हो जाता



है। किसानों ने बताया कि एक एकड़ जमीन में करेले की खेती करने में 15 से 20 हजार रुपये का खर्च आता है। जिसमें एक सीजन में 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक की आमदनी होती है। पूरे भारत में सबसे अच्छा करेला मध्यप्रदेश में मैहर जिले का ही माना जाता है। पहले यहां के किसान घर के आस पास बीज बोकर अपने

खाने के लिए करेले के पौधे लगाते थे। डिमांड के साथ अब यह पारंपरिक खेती से अलग होकर नया रूप लेता जा रहा है। यहां से करेला प्रयागराज, रीवा, जबलपुर, कटनी, बिलासपुर, उड़ीसा, कलकता, वाराणसी, कानपुर जैसी बड़ी मंडियों में थोक के भाव बिकने के लिए जाता है।

उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुनी समस्याएं, किया समाधान



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अमहिया स्थित निज निवास में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना। उप मुख्यमंत्री ने अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे नागरिकों से सहज भाव से संवाद किया और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का यथासंभव निराकरण कराया जाएगा।

जिले में अब तक 280.5 मिमी वर्षा दर्ज, बढ़ा नदियों का जल स्तर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में एक जून से अब तक 280.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। जिले में 12 जुलाई को 91.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। लगातार वर्षा के कारण बीहर, टमसर, बिछिया तथा अन्य नदियों के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई। लगातार वर्षा के कारण कई निचली बस्तियों में जल भराव हो गया। सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। जिले में 12 जुलाई को तहसील हुजूर में 205 मिलीमीटर तथा गुह में 220 मिलीमीटर वर्षा के कारण बीहर एवं बिछिया नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इस दिन सेमरिया में 48 मिलीमीटर, रायपुर कर्जुलियान में 65 मिलीमीटर, सिरमौर में 55 मिलीमीटर, ल्योथर में 20 मिलीमीटर, मनगवां में 95 मिलीमीटर तथा जवा में 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस संबंध में अधीक्षक भू-अभिलेख महेन्द्र वास्तव ने बताया कि अब तक तहसील हुजूर में 417.8 मिलीमीटर, रायपुर कर्जुलियान में 196.5 मिलीमीटर, गुह में 550 मिलीमीटर, सिरमौर में 287.6 मिलीमीटर, ल्योथर में 97 मिलीमीटर, सेमरिया में 259 मिलीमीटर, मनगवां में 297 मिलीमीटर तथा जवा में 169 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज गयी। गतवर्ष इसी अवधि में जिले में 94.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गयी थी।

राहत शिविरों में उपचार दल तैनात

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। लगातार वर्षा के कारण रीवा नगर निगम क्षेत्र के कई मोहल्लों में जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के दो वार्डों से जल भराव से प्रभावितों को चार राहत शिविरों में रखा गया है। इन शिविरों में पीड़ितों के उपचार के लिए चिकित्सा दल तैनात कर दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शुक्ला ने बताया कि राहत केन्द्र गवर्मेन्ट स्कूल क्रमांक एक में डॉ शिवशंकर मिश्रा, गवर्मेन्ट स्कूल क्रमांक दो में डॉ पीयूष सिंह, जगन्नाथ वीर में डॉ जितेन्द्र वर्मा, संस्कृत कालेज में डॉ अखिलेश कुमार सिंह तथा मार्तण्ड स्कूल में डॉ राजीवबाबू द्विवेदी को तैनात किया गया है। इनके साथ अन्य उपचार कर्मी तथा दवाएं एवं उपचार की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं।

धरती आबा जन भागीदारी अभियान कार्यक्रम का आयोजन आज

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा धरती आबा जन भागीदारी अभियान कार्यक्रम का आयोजन 13 जुलाई को सुह्रा 11 बजे से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल होंगे। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से लाभांशित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं से लाभांशित होने वाले पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित करारने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विपत्तिग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना संचालित है। योजना के तहत विपत्तिग्रस्त, पीड़ित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पाकर महिलाएं स्वयं के साथ-साथ परिवार का भी पोषण कर सकती हैं। प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन एवं पाँच सौ रुपए शिष्यवृत्ति शामिल है। जिले में योजना कलेक्टर प्रतिभा पाल के मार्गदर्शन में संचालित है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी यरन सिंह ने बताया था कि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य समूह अनुसार महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। योजना के तहत पात्र महिलाएं आगामी 25 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। योजना को आवेदन करने के संबंध में अन्य जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा वन स्टॉप सेंटर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका, दुर्व्यवहार से बचाई गई महिलाएँ, विधवा अथवा अनाथ महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हों, योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इसके साथ-साथ एसिड अटैक व्रिक्टम, जेल से रिहा महिलाएँ, परित्यक्ता, तलाकशुदा, शासकीय एवं अशासकीय नारी निकेतन, आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह, शॉर्ट स्ट्रेचमें आदि गृहों में निवासरत महिलाएं भी योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। विपत्तिग्रस्त बालिका अथवा महिलाएं, दहेज प्रताड़ित, अनि पंडित महिलाएं, बाल विवाह पीड़िता, सजायापता महिलाएँ भी योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं और प्रशिक्षण पाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रोपे गए पौधे

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वावधान में कृषि महाविद्यालय में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपण किया गया। प्राध्यापकों, कृषि वैज्ञानिकों, कर्मचारियों तथा छात्र-छात्राओं ने पौधे रोपकर इनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। पौधरोपण कार्यक्रम में अजय खरे क्षेत्रीय प्रबंधक यूबीआई, जगमोहन एलटीएम यूबीआई, डॉ. एसके त्रिपाठी अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, डॉ. बीएम मौर्या, डॉ. आरपी जोशी, डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. आरके तिवारी, डॉ. एसएम कुरुमवंशी सहित छात्र-छात्राएं शामिल रहे।

उप मुख्यमंत्री ने हास्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में वरदान मल्टीस्पेशियलिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल निःसंदेह रीवा सहित समूचे विंध्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की इस महत्वपूर्ण पहल के लिए वरदान हास्पिटल टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

विचार

जल गंगा संवर्धन अभियान’ से प्रदेश होगा जल-समृद्ध

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने अभिनव प्रयोगों से अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। मध्यप्रदेश में जल संरक्षण के लिए प्रारंभ हुआ ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दूरदर्शी पहल है। निकट भविष्य में हमें इसके सुखद परिणाम दिखायी देंगे। शुभ प्रसंग पर शुभ संकल्प के साथ जब कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है, तब उसकी सफलता के लिए प्रकृति एवं ईश्वर भी सहयोग करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर मध्यप्रदेश सरकार ने गुड़ी पड़वा (30 मार्च) से 30 जून तक प्रदेश स्तरीय ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ चलाकर जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो जनांदोलन में परिवर्तित हो गया। सरकार को भी विश्वास नहीं रहा होगा कि जल संरक्षण जैसे मुद्दे को जनता का इतना अधिक समर्थन मिलेगा कि सरकारी अभियान असरकारी बन जाएगा और समाज इस अभियान को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर स्वीकार कर लेगा। ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के अंतर्गत और इससे प्रेरित होकर प्रदेश में अनेक स्थानों पर जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया, उनको व्यवस्थिति किया गया और वर्षा जल को एकत्र करने की रचनाएं बनायी गईं। कहना होगा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल और प्रतिबद्धता ने जल संरक्षण के इस अभियान को एक जनांदोलन का रूप दे दिया है, जिससे जल संरक्षण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जल गंगा संवर्धन अभियान को गति देने के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत खेत तालाबों, अमृत सरोवरों और कूप रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है। साथ ही पुरानी जल संचनाओं का जीर्णोद्धार भी किया गया है। इस अभियान में 2 लाख 39 हजार जलदूतों का सक्रिय सहयोग मिला, जिन्होंने जल संवर्धन के संदेश को घर-घर तक पहुंचाया। ये जलदूत जब गाँव-गाँव, नगर-नगर और घर-घर जल संरक्षण का संदेश लेकर पहुँचे तो एक सकारात्मक वातावरण भी बना और जल संरक्षण को लेकर समाज के भीतर एक जागरूकता भी आई। निस्संदेह, यदि यह जनजागरूकता स्थायी हो जाए तो जल गंगा संवर्धन अभियान की सबसे बड़ी सफलता होगी। अभियान को शुरू करते समय सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था, उससे कहीं अधिक परिणाम धरातल पर प्राप्त हुआ है। जल संरक्षण के लिए 38 हजार नए खेत तालाबों का निर्माण किया गया है। खंडवा जिले में 254 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख से अधिक कुओं को रिचार्ज किया गया, जिसके लिए खंडवा को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर संभाग ने स्वच्छता और जल संरक्षण में नंबर-एक का स्थान हासिल किया है। ये दो प्रमुख उदाहरण हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। समूचे मध्यप्रदेश में 70 हजार कुओं, बावड़ियों, नदियों और तालाबों का संरक्षण किया गया, जो जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करनेवाले हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरित हैं। याद हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण के लिए जनांदोलन चलाने का आह्वान किया था। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह किया कि वह अपने स्तर पर वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रयास करे। प्रधानमंत्री मोदी की पहलकदमी पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत ‘कैच द रेन’ अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह अभियान व्यक्तियों, समुदायों और सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने तथा जल संरक्षण की पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इसी तर्ज पर ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ को जनता के बीच ले जाने का अनुकरणीय कार्य किया है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव, दोनों ही प्रकृति, पर्यावरण एवं समाज के प्रति गहरी संवेदनाएं रखते हैं। राजनीति से इतर वे इन सब विषयों पर बात रखते हैं और लोगों को इस दिशा में प्रेरित भी करते हैं। उल्लेखनीय है कि अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 120वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण को देश के लिए अत्यंत आवश्यक बताया था। उन्होंने जल संचयन जन-भागीदारी अभियान के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं

बिहार में मतदाता पहचान पत्र से जुड़े सुलगते सवालों का जवाब आखिर देगा कौन?

कमलेश पांडेय

बिहार में इसी वर्ष अटूबर-नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा जारी स्पेशल इंटेसिव रिविजन यानी एसआईआर पर पक्ष-विपक्ष आमने सामने हैं और मामला मीडिया माध्यम से आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक पहुंच चुका है। इसलिए उमीद है कि देर आयद, दुरुस्त आयद करते हुए न्यायालय ऐसे दिशा निर्देश जारी करेगा कि भविष्य में राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ से चलने वाले मतदाता सूची सबन्धी खेल पर पूर्ण विराम लग सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर न केवल आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है, बल्कि ऐसा करने से इसकी प्रक्रिया भी ज्यादा आसान होगी और विभिन्न आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी।



इस बात में कोई दो राय नहीं कि फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, किसी भी विदेशी व्यक्ति का नाम भी मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, अन्यथा मतदाता सूची की विश्वसनीयता सवालों के कठघरे में रहेगी। कोर्ट का सही मानना है कि ऐसे एसआईआर अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। जहां तक इसे लेकर संशय की स्थिति है तो आधार, राशन कार्ड या जॉब कार्ड को मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर रखने के कारण बड़ी आबादी के सामने संकट खड़ा हो गया है।

ऐसे में सुलगता सवाल है कि जिस आधार पर आप लोगों को सरकारी धनराशि से सहूलियत देते हैं, उसी महत्वपूर्ण %पहचान आधार% को आप एसआईआर में खारिज कैसे कर सकते हैं। आपके ऐसा करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की

मिलीभगत से जो संस्थागत लूट चल रही है, उसकी अब सोशल ऑडिट जरूरी है, क्योंकि इस मामले में पक्ष-विपक्ष सभी शामिल हैं। सच कहूँ तो इससे भारत के उन मूल निवासियों को क्षति हो रही है जिनका देश की सरकार और संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए।

हमारा आशय उस हिन्दू वर्ग से है जो धार्मिक आधार पर राष्‍ट्र विभाजन के बाद भी राजनीतिक व संवैधानिक षडयंत्र का शिकार होता आया है। जब पाकिस्तान व बांग्लादेश इस्‍लामीकरण की राह पर बढ़ रहे हैं तो भारत की धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के साथ बेमानी प्रतीत हो रही है। आलम यह है कि मुस्लिम नेता पाकिस्तान व बांग्लादेश से मुसलमानों को बुलाकर यहां बसा रहे हैं और उन्हें सरकारी पहचान पत्र दिलवाने में मदद कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने-टोकने की प्रशासनिक विफलता या मिलीभगत से कई सवाल पैदा हो रहे हैं, जो हिंदुओं के दूरगामी हित के लिए से चेतावनी दे रहे हैं।

ऐसे में एसआईआर की जरूरत है। साथ ही, सरकारी

पहचान पत्र बनवाने और उससे लाभान्वित होने के पूरे खेल की समीक्षा हो और जिम्मेदार अधिकारियों, नेताओं और उनके दलों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो, कि उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे, राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त हो और अधिकारियों-कर्मचारियों की बर्खास्तगी की जाए। क्योंकि ये लोग भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केवल किशनगंज जिले में एक हफ्ते के भीतर निवास प्रमाण पत्र के लिए दो लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। कई जगह घर-घर जाकर इंग्लिश फॉर्मस बांट रहे कर्मियों ने लोगों से कहा है कि वे आधारकार्ड की कॉपी ही जमा करा दें। लिहाजा ऐसे कंप्यूजन से बेहतर है कि आयोग बीच का रास्ता निकाले।

जहां तक एसआईआर के समय पर सवाल है तो शीर्ष अदालत ने स्पेशल इंटेसिव रिवीजन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन इसके समय को लेकर जो सवाल उठाया, वह बिल्कुल वाजिब है। ऐसा इसलिए कि बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। लिहाजा बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह इसका समय भी है। जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे।

हालांकि आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वहीं, जहां तक नागरिकता पर फैसला का सवाल है तो बताया गया है कि इस अभियान का उद्देश्य ऐसा नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है और लोकतंत्र में सबसे अहम है लोक यानी जनता। लेकिन, चुनाव आयोग की मौजूदा प्रक्रिया में जनता को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। यह रिवीजन जुड़ा है वोटर लिस्ट से, लेकिन मैसेज जा रहा है कि इससे नागरिकता तय होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से राहत मिलेगी कि निर्वाचन आयोग का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि, इतना तो तय है कि इस एसआईआर अभियान का असर अब पूरे देश पर पड़ेगा। ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जबतक संविधान में अमूलचूल बदलाव नहीं होगा तबतक इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने में मुश्किल आएगी। क्योंकि यह मामला केवल बिहार तक सीमित रहने वाला नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों में वोटर लिस्ट की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। क्योंकि अगला नम्बर पश्चिम बंगाल और असम का आएगा जहां अगले साल चुनाव होंगे।

ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आधिकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है। इसी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के इस्लामीकरण का यह परोक्ष अभियान निकट भविष्य में थमेगा या जारी रहेगा। क्योंकि इसके तार अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र से जुड़े हुए हैं। अमेरिका-पाकिस्तान-चीन दशकों से इस कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि हमारी सरकारें भी अपने वोट बैंक के लिहाज से काम करती आई हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के हिसाब से नहीं। खासकर 15 अगस्त 1947 के बाद उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति से!

होना तो यह चाहिए कि भारत सरकार का जनसंख्या रजिस्टर ऑनलाइन हो। उसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि इस ग्राम या मोहल्ले का फलां व्यक्ति अब फलां जगह के लिए पलायन कर गया है। उसका एक जन्म प्रमाण पत्र बने जो पूरे देश में लागू हो। मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बने। सभी दस्तावेज इसी आधार पर बनें और पूरे देश में लागू हों। बैंक भी उसी आधार पर खाता खोलें। आज राशन कार्ड, मजदूर जॉब कार्ड, आधार कार्ड की आड़ में जो संस्थागत लूट चल रही है, वह रुके। लेकिन रोकेंगे कौन? जो भ्रष्ट हैं, जांच का जिम्मा उनसे लेकर अन्य को दिया जाए। सोशल ऑडिट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डीएम, एसडीएम की ऐसी लापरवाहियों के लिए स्थायी जांच एजेंसी बने। उसकी रिपोर्ट राजनीतिक दांवपेंच से बाहर रखकर लागू करने का प्रावधान बने। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि बिहार में मतदाता पहचान पत्र से जुड़े सुलगते सवालों का जवाब आखिर देगा कौन?

बोलसेनारो को माफी देने से लूला ने किया इंकार तो यूएस ने किया पलटवार

नीरज कुमार दुबे

अमेरिका द्वारा ब्राजील पर नए टैरिफ लगाए जाने के घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति में निजी संबंधों और वैचारिक द्वंद्व की अहमियत को एक बार फिर उजागर कर दिया है। यह व्यापारिक निर्णय उस संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैयर बोलसेनारो के संबंधों तथा वर्तमान ब्राजीली राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की राजनीतिक सोच से जोड़कर देखा जाए। हम आपको बता दें कि तमाम आरोपों का सामना कर रहे बोलसेनारो भागे भागे फिर रहे हैं। ट्रंप ने अपने मित्र का बचाव करने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति से जो आग्रह किया उसे ठुकरा दिया गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति आग बबूला हो गये और टैरिफ लगा दिये। हम आपको बता दें कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैयर बोलसेनारो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वैचारिक और व्यक्तिगत संबंध जगजाहिर हैं। दोनों दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं और दोनों ने अपनी-अपनी सरकारों में वैश्वीकरण, पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं और वामपंथी आंदोलनों का मुखर विरोध किया। ट्रंप ने बोलसेनारो को ट्रॉपिकल ट्रंप तक कहा था और ब्राजील में उनके शासनकाल के दौरान अमेरिका-ब्राजील संबंधों को घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया।2022 में जब वामपंथी नेता लूला ने बोलसेनारो को हराकर सत्ता में वापसी की, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि एक वैचारिक पलटवार भी था। लूला ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने 2023 की शुरुआत में हुई ब्राजील की राजधानी में बोलसेनारो समर्थकों द्वारा लोकतंत्र पर हमले को ट्रंप समर्थित अमेरिकी विद्रोह की तर्ज पर देखा और

इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की।

जब अमेरिका की ओर से दबाव आया कि ब्राजील, बोलसेनारो को राजनीतिक या कानूनी संरक्षण दे, तो लूला ने स्पष्ट शब्दों में माफी या विशेष राहत देने से इंकार कर दिया। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने ब्राजील से आयातित स्टील और अन्य उत्पादों पर टैरिफ (शुल्क) बढ़ा दिया। यह कदम औपचारिक रूप से व्यापारिक कारणों से उठाया गया बताया गया, लेकिन समय और संदर्भ को देखते हुए यह एक राजनीतिक दंड जैसा प्रतीत होता है।

देखा जाये तो यह टैरिफ विवाद, दरअसल ट्रंप और लूला के बीच की गहरी वैचारिक खाई का विस्तार है। जहां ट्रंप दुनिया में राष्ट्रवादी और संरक्षणवादी विचारों को बढ़ावा देते हैं, वहीं लूला बहुपक्षीय सहयोग और सामाजिक न्याय के वैश्विक एजेंडे का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्राजील के बीच यह व्यापारिक तनाव केवल आर्थिक न होकर राजनीतिक दबाव की रणनीति का हिस्सा भी बनता है।

इस घटनाक्रम से जो महत्वपूर्ण संकेत निकलते हैं वह यह हैं कि व्यक्तिगत रिश्ते अब कूटनीति का नया आयाम बन चुके हैं। साथ ही सरकारों के बीच रिश्ते अब केवल संस्थागत नहीं रहे, नेताओं की वैचारिक संगति या टकराव इन रिश्तों को दिशा दे रही है।

इसके अलावा, लूला दक्षिण अमेरिका में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं और वह अमेरिकी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। लूला ने ट्रंप के आग्रह को ठहराते हुए दो टुक कहा था कि ब्राजील के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी नेता का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। यह वक्तव्य न केवल ब्राजील की संप्रभुता के प्रति लूला की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट



करता है कि वह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेंगे।

इसके अलावा, हाल ही में कुछ अमेरिकी और दक्षिणपंथी मीडिया रिपोर्टों में यह चर्चा थी कि ट्रंप प्रशासन से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसेनारो के पक्ष में बयानबाजी की और उन्हें क़राजनीतिक उत्पीड़नक़ा शिकार बताया। इस संदर्भ में लूला का कड़ा बयान यह स्पष्ट करता है कि ब्राजील के कानूनी संस्थानों और राजनीतिक प्रक्रिया को बाहरी दबाव में नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि जो व्यक्ति (बोलसेनारो) लोकतंत्र को कमजोर करने का दोषी

है, उसे कानून के अनुसार दंड मिलेगा, चाहे उसके समर्थन में कोई भी अंतरराष्ट्रीय नेता क्यों न बोले।

हम आपको बता दें कि बोलसेनारो, जो ब्राजील के दक्षिणपंथी नेता और पूर्व राष्ट्रपति हैं, वह वर्तमान में कई आपराधिक जांचों का सामना कर रहे हैं। उन पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि 2022 के चुनाव में हार के बाद बोलसेनारो ने चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 8 जनवरी 2023 को ब्रासीलिया स्थित संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर उनके समर्थकों ने हिंसक हमला किया, जो अमेरिका में हुई कैपिटल हिल घटना की याद दिलाता है। बोलसेनारो पर इस

हमले को भड़काने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप है।

इसके अलावा, एक अन्य आरोप है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बोलसेनारो ने वैक्सीनेशन को लेकर गलत जानकारी फैलाई। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा किया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति मिल सके।

बोलसेनारो और उनकी पत्नी पर यह आरोप भी लगा है कि उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सऊदी अरब से मिले बेशकीमती गहनों को निजी संपत्ति मानते हुए ब्राजील से बाहर ले जाने की कोशिश की। इन सभी आरोपों के चलते बोलसेनारो पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। वह कुछ समय तक अमेरिका में शरण लिए हुए थे, जिससे यह संदेश गया कि वह गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। हालांकि अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, परंतु न्यायालय और संघीय जांच एजेंसियां उन पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

बहरहाल, अमेरिका द्वारा ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों का प्रतीक हैं। ट्रंप और बोलसेनारो की नजदीकी तथा लूला की वैचारिक दृढ़ता इस संघर्ष को केवल दो राष्टों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष बना देती है। आने वाले दिनों में इस बात पर नजर बनी रहेगी कि क्या ब्राजील इस दबाव के सामने झुकेगा या फिर यह टकराव वैश्विक शक्ति-संतुलन को नई दिशा देगा। वैसे यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि ब्राजील अब संप्रभुता, लोकतंत्र और न्याय के मार्ग पर किसी भी प्रकार की बाहरी दखलअंदाज़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

जिले में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश के कारण नदी-नालों के जल स्तर में तेजी से हुई वृद्धि

कलेक्टर ने जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों तथा राहत शिविरों का किया निरीक्षण, प्रभावितों का सर्वे करने के दिये निर्देश



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश के कारण नदी-नालों के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। जिले में 12 जुलाई को गुढ़ तहसील में 220 मिलीमीटर और हुजूर तहसील 205 मिलीमीटर वर्षा होने के कारण बीहर नदी का जल स्तर बढ़ गया है। रीवा में बीहर नदी दोपहर 3 बजे खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही थी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और बचाव के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने बीहर नदी के छोटी पुल, करहिया घाट, करहिया पुल तथा अन्य जगहों का दौरा किया। कलेक्टर ने जल भराव से प्रभावित व्यक्तियों के लिए गवर्मेंट स्कूल गुढ़ चौराहा में बनाए गए दो राहत केंद्रों का निरीक्षण कर पीड़ितों से मुलाकात की। इसमें वार्ड क्रमांक 40 और 44 के नई बस्ती क्षेत्र के 26 परिवारों के 88 लोगों को रखा गया है। राहत केंद्र में प्रशासन तथा नगर निगम द्वारा पीड़ितों के लिए आवास, पानी, नाश्ता, उपचार की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने जल भराव से पीड़ितों से राहत केंद्र में दी गई सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को नाश्ता, भोजन और पानी की समुचित



व्यवस्था के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शुक्ला को राहत केंद्रों में उपचार दल तैनात करने के निर्देश दिए। गवर्मेंट स्कूल में नगर निगम के प्रभारी शहरी आजीविका परियोजना अभिमन्यु सिंह तथा उपयुक्त एसएम सिद्दीकी द्वारा पीड़ितों के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश ताण्डेकर को जल भराव से पीड़ितों के लिए खाद्यान्न का वितरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम हुजूर वैशाली जैन को जल

भराव से प्रभावित वार्ड क्रमांक 40 के घरों का आज ही सर्वे करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सर्वे में यदि किसी तरह की हानि दर्ज होती है तो शासन के मापदण्डों के अनुसार राहत राशि का प्रकरण तत्काल दर्ज करके पीड़ितों को राहत राशि दें। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि कंट्रोल रूम में जिम्मेदार अधिकारी 24 घंटे तैनात रहें। तहसीलों के कंट्रोल रूम जल संसाधन विभाग, बाणसागर बांध, बकिया तथा टमस बराज से

लगातार सूचनाएं प्राप्त करते रहें। प्राकृतिक आपदा के समय में यदि कोई व्यक्ति मदद के लिए फोन करता है तो तत्काल संबंधित अधिकारी को सूचित करें। किसी भी गांव में जल भराव अथवा बाढ़ की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित क्षेत्र के जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव तथा पटवारी को सूचना दें। सूचनाएं देने में किसी भी तरह की देरी होने पर कार्यवाही की जाएगी। मैहर, सतना और अमरपाटन के कंट्रोल रूम से भी संपर्क में रहकर वर्षा की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें।

कलेक्टर ने नगर निगम में स्थापित कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मौके पर उपस्थित कंट्रोल रूम प्रभारी मुरारी प्रसाद ने बताया कि कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहते हैं। जल भराव से निपटने के लिए 12 जेसीबी मशीनें, एक पोकलेन मशीन, पानी निकालने के लिए चार पंप सहित राहत और बचाव की टीमें तैनात हैं। शहर में 19 स्थानों पर बाढ़ से प्रभावितों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें से चार स्थानों गवर्मेंट स्कूल क्रमांक एक एवं दो, जगन्नाथ मंदिर तथा

उप मुख्यमंत्री ने रानी तालाब क्षेत्र में जल भराव पीड़ितों से की भेंट



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले और शहर में लगातार बारिश होने से शहर के कई वार्डों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रानी तालाब क्षेत्र का भ्रमण कर जल भराव की स्थिति का जायजा लिया तथा पीड़ितों से भेंट की। उप मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से कहा कि जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा पीड़ितों के लिए 13 स्थानों पर राहत शिविर स्थापित कर दिए गए हैं। इनमें से चार शिविरों में वार्ड क्रमांक 40 और वार्ड क्रमांक 44 के पीड़ितों को रखा गया है। इनमें भोजन, पानी, उपचार आदि की पूरी सुविधा दी गई है। नगर निगम

की टीम शहर भर में जल भराव को दूर करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। नगर निगम में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसमें 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। वर्षा का जोर कम हो गया है। अब जल भराव की समस्या दूर हो जाएगी। बीहर नदी के जल स्तर में भी धीरे-धीरे कमी आ रही है। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए समुचित उपाय के निर्देश दिए।

खैरी बस्ती तथा झिरिया में जल भराव से प्रभावित 33 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में 11 जुलाई को रात में भारी वर्षा होने से रीवा नगर निगम के कई वार्डों में निचली बस्तियों में जल भराव हो गया। जिला कंट्रोल रूम तथा नगर निगम कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होने पर होमगार्ड के जवानों तथा एसडीआरएफ की टीम ने चोरहटा थाना क्षेत्र के तहत ग्राम खैरी की निचली बस्ती में जल भराव में फंसे 23 लोगों को सुरक्षित निकाला। इसी तरह झिरिया नाला के किनारे भी घरों में जल भराव होने पर 10 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस संबंध में जिला सेनानी होमगार्ड मीना सिंह ने बताया कि जल भराव से किसी भी तरह की जनधन की हानि नहीं हुई है। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित कर दिया गया है। प्लाटून कमाण्डर विकास पाण्डेय की टीम ने राहत और बचाव का कार्य किया।



त्योथर क्षेत्र में भी होमगार्ड के जवान नाव तथा अन्य उपकरणों के साथ

किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात हैं। प्राकृतिक आपदा के संबंध

में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है।

वर्षा प्रभावितों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की टीम तैनात

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में 11 जुलाई को दिन तथा रात में लगातार बारिश होने से कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। रीवा नगर निगम में घरों तथा निचली बस्तियों से जल भराव से निपटने के लिए नगर निगम की टीम लगातार प्रयास करती रही। ग्राम रौसर में एक घर में पानी भरने की सूचना मिलने पर जनपद तथा होमगार्ड कर्मचारियों ने पहुंचकर जल निकासी की व्यवस्था कराई। लगभग दो घंटों के प्रयासों के बाद जल भराव की समस्या दूर हुई। लगातार बारिश के कारण डभौरा में मकान क्षतिग्रस्त हो गया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एसडीएम तथा तहसीलदार को तत्काल क्षतिग्रस्त मकान का सर्वे करके राहत राशि का प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। मंगवां तहसील में ग्राम नदहा में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए जनपद और राजस्व विभाग की टीम ने लगातार प्रयास किया। एसडीएम संजय जैन ने नदहा मोड़ तथा मेथोरी में पाइप लगाकर जल निकासी की व्यवस्था कराई। त्योथर तहसील के ग्राम चंदई में तहसीलदार



ने अतिक्रमण हटाकर जेसीबी से जल निकासी की व्यवस्था कराई। नायब तहसीलदार लालन सिंह ने जनपद और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के सहयोग से ग्राम मझियार में स्कूल परिसर तथा उसके सामने जल भराव की समस्या को दूर कराया। ग्राम पटना में जल भराव को दूर करने के लिए नायब तहसीलदार दिलीप वास्तव ने जेसीबी से कटाव कराकर जल

निकासी कराई। ग्राम रौरा और खीरा में भी बस्तियों से जल भराव को नाली बनाकर दूर किया गया। ग्राम सिरिखनी, चौराड़ी तथा मढ़ीकला में भी जल भराव की समस्या को दूर किया गया। राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जनपद तथा ग्राम पंचायत के कर्मचारी एवं होमगार्ड के जवान राहत और बचाव का कार्य तत्परता से कर रहे हैं। जल प्रपातों में भी गांव में अभी बाढ़ का खतरा नहीं है।

होमगार्ड के कर्मचारी तैनात करके लोगों को खतरनाक क्षेत्रों में न जाने के लिए सचेत किया जा रहा है। क्योटी जल प्रपात में जनपद पंचायत गोव और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा लगातार एनाउंसमेंट किया जा रहा है। जिले भर में अच्छी वर्षा तथा मैहर एवं सतना में वर्षा के कारण टमस नदी में भी पानी की आवक बढ़ गई है। बीहर बराज तथा बकिया बराज के 13 गेट आधी ऊंचाई तक खोलकर नियंत्रित रूप से पानी की निकासी की जा रही है। टमस और बीहर नदियों में अधिक मात्रा में पानी आने से त्योथर क्षेत्र में कई स्थानों पर टमस नदी के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। त्योथर में टमस नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 5 मीटर नीचे है। सितलहा पुल पर शाम 3 बजे से पानी जाने के कारण बैरियर लगाकर आवागमन बंद कर दिया गया है। एसडीएम पीपुष भट्ट ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल के दोनों होमगार्ड सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। त्योथर क्षेत्र के किसी भी गांव में अभी बाढ़ का खतरा नहीं है।

आपदा प्रबंधन के लिए कलेक्ट्रेट और नगर निगम में कंट्रोल रूम चालू

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति से निपटने तथा विभिन्न विभागों में समन्वय के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं नगर निगम में कंट्रोल रूम जून माह से ही स्थापित कर दिए गए हैं। इनमें 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। इनके द्वारा लगातार सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम का फोन नम्बर 07662-255143 है। इसमें वर्षा के संबंध में लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। आमजनता अतिवृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदा में कंट्रोल रूम को सूचना दें। सूचना मिलने पर तत्काल राहत और बचाव की कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम रीवा में भी नवीन भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी बाढ़ अथवा अन्य आपदा होने पर टोलफ्री नम्बर 18008899711 पर सूचना देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ-साथ कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 07662-310346,



320105, 320150 अथवा 254568 पर भी फोन करके आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी 12 जेसीबी मशीन, जल निकासी के लिए पंप तथा अन्य उपकरणों के साथ 24 घंटे उपलब्ध हैं। जिला पंचायत में भी बाढ़ नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर इसमें 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसका फोन नम्बर 07662-252607 है। इसका प्रभारी अधिकारी स्मिता खरे परियोजना अधिकारी को बनाया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए एलटी सिंह को भी तैनात किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जल भराव अथवा अन्य आपदाओं के समय जिला पंचायत के कंट्रोल रूम को सूचना देकर आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत



एक गंभीर रूप से घायल रीवा रेफर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में शनिवार को तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। हादसा एनएच-39 पर कदैला के पास हुआ, जिसमें दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रामपुर बघेलान क्षेत्र के कदैला स्थित बंसल पेट्रोल पंप के पास हुआ। बाइक सवार तीन युवक अपने गांव पैपखरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक ट्रक से पीछे से टकरा गई। ट्रकर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के

परखच्चे उड़ गए और दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनीष आदिवासी (निवासी नेमुआ) और रामलखन आदिवासी (निवासी पैपखरा) के रूप में हुई है। हादसे में तीसरा युवक सुरज आदिवासी (निवासी पैपखरा) गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हावसे से रीवा-सतना मार्ग पर लगा जाम: हादसे के बाद सतना-रीवा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही रामपुर बघेलान थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया और ट्रैफिक सुचारू कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सड़क की कमी से हुई मौत, महिला ने रास्ते में तोड़ा दम



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना के नागोद विकासखंड के द्वारी ग्राम पंचायत के हनुमान टोला में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने एक महिला की जान ले ली। शनिवार को भूरा चौधरी की 65 वर्षीय पत्नी कल्लू बाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कच्चे रास्ते और बारिश के कारण कीचड़ होने से कोई वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। परिजन और ग्रामीण उन्हें खाट पर लेकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कल्लू बाई ने दम तोड़ दिया।

हनुमान टोला, जो द्वारी खुर्द और ररा गांव के बीच स्थित है, में करीब 15 परिवार रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के 78 साल बाद भी इस क्षेत्र में पक्की सड़क नहीं बनी है। एक दशक पहले तत्कालीन सरपंच सुभद्रा गौड़ ने रोजगार गारंटी योजना के तहत मिट्टी का रास्ता बनवाया था, लेकिन उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। बारिश में खेतों के बीच का यह कच्चा रास्ता कीचड़

से भर जाता है, जिससे बीमारों और गर्भवती महिलाओं को खाट पर ले जाना पड़ता है।

शनिवार को कल्लू बाई की तबीयत बिगड़ने पर एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। 500 मीटर के कच्चे रास्ते ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को असंभव बना दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आम हैं, जहां सड़क की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता।

यह क्षेत्र रैगांव विधानसभा में आता है, जहां से भाजपा विधायक और प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी हैं। ग्रामीणों ने मंत्री के क्षेत्र में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा की कमी पर रोष जताया और प्रशासन से तत्काल पक्की सड़क निर्माण की मांग की है।

इस घटना ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर किया है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि ऐसी मिट्टी का रास्ता बनवाया था, लेकिन उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। बारिश में खेतों के बीच का यह कच्चा रास्ता कीचड़

सतना में किशोर का फंदे पर मिला शव, सौतेली मां और बहन पर हत्या का आरोप



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पतेरी इलाके में शुक्रवार रात 17 वर्षीय किशोर प्रशांत सेन ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजन इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या बता रहे हैं और सौतेली मां-बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

परिवार का आरोप है कि घर लौटने पर उससे जबरन पैसे ले लिए जाते थे और उसे अपमानित किया जाता था। ननिहाल पक्ष का दावा है कि वह आत्महत्या नहीं कर सकता, उसे मारकर फांसी पर लटकाया गया है।

मृतक के मामा ने सिविल लाइन थाना में सौतेली मां और बहन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

प्रजांत मजदूरी कर घर का खर्च चलाने की कोशिश करता था।

आवासीय परिसर में गैर घरेलू गतिविधियां होने पर व्यवसायिक श्रेणी में विद्युत कनेक्शन के लिए स्वेच्छिक आवेदन करने की सलाह

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पैइंग गेस्ट, प्रायवेट हॉस्टल या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, उन्हें कंपनी ने सलाह दी है कि वे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपने प्रयोजन को घरेलू से गैर घरेलू (व्यवसायिक) श्रेणी में परिवर्तित करवा लें। कंपनी ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए विद्युत कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपभोग करें। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू लाइट और फैन का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने बताया कि सघन चैकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही है तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने कनेक्शन की जांच करा लें और जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया गया है उसी के अनुसार सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए बिजली कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल पर जाकर अपने कनेक्शन प्रयोजन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित टैरिफ श्रेणी में परिवर्तित करा लें।

टेनिस प्लेयर राधिका मर्डर, पिता की थ्योरी पर 7 सवाल

गुरुग्राम (एजेंसी)। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की पिता दीपक यादव ने 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। एक गोली कंधे पर और 3 गोलियां उसकी छाती के बराबर पीठ पर लगीं। हत्या के बाद पिता ने कहा कि लोग उसे ताना मारते थे कि बेटी की टेनिस एकेडमी की कमाई खा रहा है। उसने बेटी को एकेडमी बंद करने को कहा था। वह नहीं मानी तो गोली मार दी। गुरुग्राम पुलिस के गले पिता की यह थ्योरी नहीं उतर रही है। राधिका की मां चुप है। पिता के बयान से लेकर मां की चुप्पी तक कई ऐसे सवाल हैं, जो हाई प्रोफाइल बन चुके इस हत्याकांड की वजह को लेकर संदेह पैदा कर रहे हैं। सबसे हेरानी पुलिस को इस बात से है कि इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर और एक टेनिस एकेडमी चलाने के बावजूद राधिका का कोई सोशल मीडिया अकाउंट क्यों नहीं है? ऐसे में सवाल है कि क्या उससे अकाउंट डिलीट कराए गए? ऐसे ही कई सवाल इस केस को लेकर उठ रहे हैं, जो इस हत्याकांड को पेचीदा बना रहे हैं...

गुजरात महिसागर पुल हादसा- मरने वालों की संख्या 21 हुई

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बने पुराने पुल के ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। शुक्रवार को एक घायल की अस्पताल में मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 20 हो गया है। एक शख्स की तलाश में टीमें जुटी हैं। वडोदरा कलेक्टर अनिल धमेलिया ने कहा- नदी में गिरे एक ट्रैक्टर में सल्यूरिक एसिड भरा था। ऐसे में पता लगाया जा रहा है कि उसमें से कोई रिसाव तो नहीं है। वहीं पानी सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट) होने के कारण रेस्क्यू टीम को जलन और खुजली हो रही है। हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पुल ढहने के सिलसिले में राज्य के सड़क एवं भवन विभाग के चार इंजीनियरों को निर्लंबित कर दिया है। हादसे की शुरुआती जांच में पाया गया कि पुल की नींव और जोड़ कमजोर हो चुके थे, जिससे यह हादसा हुआ। जांच समिति 30 दिन में पूरी रिपोर्ट देगी। महिसागर नदी पर बना ब्रिज 9 जुलाई की सुबह ढूट गया था।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों के लिए 2.70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये जारी की गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। विभाग द्वारा 19 जून को जारी विज्ञापन के तहत कुल 19,504 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अब तक 2,70,152 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया में दस संभागों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 55,730 और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 2,14,422 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 4 जुलाई



निर्धारित की गई है, जबकि भरे गए आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। उल्लेखनीय है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 19 हजार 504 पदों की पूर्ति के लिए इंदौर संभाग से सबसे अधिक 47 हजार 116 आवेदन प्राप्त

हुए हैं जिन में 38 हजार 601 सहायिका के पद और 8 हजार 515 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। जबलपुर संभाग से कुल 44 हजार 258 आवेदन में से 34 हजार 317 सहायिका के और 9 हजार 941 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के आवेदन प्राप्त हुए

है। सागर संभाग से 33 हजार 513 में से सहायिकाओं के पद के लिए 27 हजार 857 और कार्यकर्ता के लिए 5 हजार 656 आवेदन आए हैं। भोपाल में कुल 28 हजार 850 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें सहायिका के पद के लिए 22 हजार 397 और कार्यकर्ता के लिए 6 हजार 453 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार रीवा से 28 हजार 519 कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 23 हजार 831 आवेदन सहायिका के और 4 हजार 688 आवेदन कार्यकर्ता के लिए प्राप्त हुए हैं। ग्वालियर संभाग के 28 हजार 413 आवेदनों में सहायिका के 22 हजार 73 और कार्यकर्ताओं के 6 हजार 340 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

नए डीएवी एसीसी पलिक स्कूल के नए भवन और हेरिटेज विंग का उद्घाटन किया

मीडिया ऑडीटर, कयमोर (एजेंसी)। नए डीएवी एसीसी पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग और एक हेरिटेज विंग %कल्पशिला% का आज अदाणी समूह के सीमेंट व्यवसाय के सीईओ श्री विनोद बाहेती द्वारा अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के निदेशक मंडल की सम्मानित उपस्थिति में सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि, सामुदायिक विकास के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता के तहत अदाणी फाउंडेशन द्वारा समर्थित है, तथा यह संस्थान की व्यापक शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण को सुदृढ़ करती है। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तिलक समारोह और विशिष्ट अतिथियों के गर्मजोशी



से स्वागत के साथ हुई। इसके बाद, छात्रों ने मध्य प्रदेश लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस यात्रा के दौरान अतिथियों ने डीएवी स्कूल में समग्र शिक्षा के प्रतीक एक मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद छात्रों ने द्रोणाचार्य और एकलव्य की लीलाओं का मनमोहक प्रदर्शन किया, जिसमें शिष्य के अथाह त्याग और गुरु-

शिष्य परंपरा के चिरस्थायी महत्व पर जोर दिया गया। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों ने कल्पशिला का दौरा किया और वहां के विविध रचनात्मक और मनोरंजक स्थानों का अवलोकन किया, जिनमें संगीत कक्ष, कला कक्ष और खेल कक्ष शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक ने समुदाय के भीतर जीवंत गतिविधियों और प्रतिभाओं के

बारे में जानकारी प्रदान की। एक पौधारोपण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों ने विकास और स्थिरता के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में पौधे लगाए, पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला, यह एक ऐसी पहल है जिसे अदाणी फाउंडेशन का पुर्जोर समर्थन प्राप्त है। अंत में अतिथियों को नवनिर्मित भवन का भ्रमण कराया गया, जिसमें छह आधुनिक कक्षाएं, एक समर्पित शिक्षक संसाधन केंद्र और एक सम्मेलन कक्ष हैं। उन्होंने छात्रों द्वारा प्रदर्शित प्रभावशाली प्रदर्शनीयों का भी अवलोकन किया, जिनमें उनके नवोन्मेषी मॉडल और परियोजनाएं प्रदर्शित थीं।

संसाधन केंद्र और एक सम्मेलन कक्ष हैं। उन्होंने छात्रों द्वारा प्रदर्शित प्रभावशाली प्रदर्शनीयों का भी अवलोकन किया, जिनमें उनके नवोन्मेषी मॉडल और परियोजनाएं प्रदर्शित थीं।

कल के शहरों का निर्माण प्रदर्शनी का उद्घाटन

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 अंतर्गत कल के शहरों का निर्माण थीम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए संचालित विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से विकसित सुदृढ़ अधोसंरचना, नवाचारों, निवेश प्रोत्साहन नीतियों एवं योजनाओं से संबंधित प्रकल्प प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहना की।

प्रदर्शनी में इंदौर विकास प्राधिकरण की अधोसंरचना विकास के लिए अपनाए गए मॉडल जिसमें पीपीपी मॉड पर आधारित बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स पार्क के निर्माण, एयरपोर्ट के पास कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए निर्माणाधीन स्टार्टअप पार्क को प्रकाशित किया गया। प्रदर्शनी में सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी को डिजिटली उपलब्ध कराने के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डिजिटल व्यवस्था देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। कल के शहरों के निर्माण में मेट्रो रेल की भूमिका को दर्शाने वाली प्रदर्शनी में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना (येलो लाइन), भोपाल मेट्रो रेल परियोजना (ऑरेंज और ब्लू लाइन), रोलिंग स्टॉक (ट्रेन) देशी तकनीक से निर्मित आधुनिक



मेट्रो ट्रेनों, सूचनात्मक पैनल को प्रदर्शित किया गया जिसके माध्यम से कल के शहरों में आवागमन के सशक्त साधन को दिखाया गया है। टेक्नोलॉजी आधारित विकास की पांच परिवर्तनकारी नीतियां आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2023, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (नष्ट) नीति 2025, ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति 2025, एवीजीसी-एक्सआर (एनीमेशन, विजुअल

इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) नीति 2025, सेमीकंडक्टर नीति 2025 का प्रदर्शन किया। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम इंदौर द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई जिसमें राज्य के प्रमुख अधोसंरचना परियोजना के गतिशील औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, तेजी से विकसित होती आईटी अवसंरचना, और समावेशी शहरी विकास को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में

विशेष रूप से इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईटी पार्क-3, इंदौर, आईटी पार्क-4, सुपर कॉरिडोर, इंदौर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, रेडिमेड गार्मेंट कॉम्प्लेक्स में प्लग एंड प्ले सुविधा को प्रदर्शित किया गया।

32 साल की सेवा करने के बाद भी नहीं मिली ग्रेजुटी-पेंशन राशि

भोपाल। कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीडित में 30 से 35 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारी आज भी ग्रेजुटी और पेंशन से वंचित हैं। 2023-24 तक यहां 96 कर्मचारी कार्यरत थे। सभी को केंद्र सरकार के वेतनमान और भत्तों का लाभ मिला। भविष्य निधि और अर्जित अवकाश की पात्रता भी दी गई। सेवा निवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों को ग्रेजुटी और पेंशन नहीं मिली। यह विभाग शुरू से ही केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। नियम के अनुसार 10 साल सेवा के बाद कर्मचारी ग्रेजुटी और पेंशन का हकदार होता है। यहां 32 साल सेवा देने के बाद भी कर्मचारी वंचित हैं। वर्ष 2020 से 2025 के बीच रिटायर 15 से ज्यादा कर्मचारियों के परिवार आज भी आर्थिक तंगी में हैं।

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क की गुणवत्ता पर उठे सवाल

भोपाल। देश के सबसे आधुनिक कौशल विकास संस्थानों में गिने जाने वाले संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क (स्क्रन्नस्क) को लेकर अब गंभीर तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी खामियां उजागर हो रही हैं। महज एक वर्ष पूर्व चालू हुई इस परियोजना में भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कर्मचारियों और छात्रों ने गंभीर चिंताएं जताई हैं।



सूत्रों के अनुसार, पार्क के कई भवनों में छटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। छात्रावास और शैक्षणिक भवनों की हालत भी संतोषजनक नहीं है। संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों ने बताया कि कई स्थानों पर दीवारों में सीलन, फर्श में दरारें और छत से रिसाव

जैसी समस्याएं नियमित रूप से देखने को मिल रही हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जताई चिंता, हटाने की सिफारिश: इस परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 21200 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया था। अब, षष्ठ के संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र भेजकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है और निर्माण कार्य से जुड़े सिविल निदेशक को तत्काल प्रभाव से हटाने की सिफारिश की है। बैंक को आशंका है कि निर्माण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की संभावनाएं रही हैं।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। लाख बच्चे नामांकित हैं। प्रदेश में ड्रॉप-आउट

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा में मातृ-भाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है।



श्री प्रधान ने यह बात बुधवार को भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह से सौजन्य मुलाकात के दौरान कही। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री? सिंह ने बताया कि प्रदेश में 4473 शासकीय स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इन शालाओं में करीब एक

बच्चों की संख्या दर कम करने के लिए स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी दी।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर को 5 वर्ष की सजा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निदेश पर प्रदेश में वन एवं वन्य-जीव संरक्षण के लिये किये जा रहे समग्र प्रयासों के अंतर्गत वन विभाग की स्टेट टाइगर फोर्स भोपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा, जो मूल रूप से तिब्बत का निवासी है, जिसे 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद 25 जनवरी, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत-नेपाल के पास सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। स्टेट टाइगर फोर्स द्वारा की गयी सटीक विवेचना एवं न्यायालय में रखे गये ठोस पक्ष के आधार पर आरोपी शेरपा को 9 मई, 2025 को 5 वर्ष की सजा दी गयी। इंटरपोल मुख्यालय ल्योन, फ्रांस से जारी पत्र में मध्यप्रदेश वन विभाग की स्टेट टाइगर फोर्स को अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा के सफलतापूर्वक अभियोजन पूर्ण कर सजा दिलवाने की उत्कृष्ट कार्रवाई के लिये बधाई-पत्र भेजा है। इंटरपोल जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी नियंत्रण पुलिस संगठन कहा



जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो 195 से अधिक देशों ने मिलकर बनाया है। यह पूरे विश्व में पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। मध्यप्रदेश वन विभाग ने स्टेट टाइगर फोर्स का गठन केन्द्र शासन के निदेश पर वन्य-जीवों की तस्करी की रोकथाम के लिये किया है। स्टेट टाइगर फोर्स ने विगत कुछ वर्षों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इससे पहले भी

इंटरपोल द्वारा 3 बार एसटीएसएफ के कार्यों की सराहना की जा चुकी है। अपराधी ताशी शेरपा अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका नेटवर्क भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। जुलाई-2024 में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ताशी शेरपा की जमानत याचिका को खारिज कर ट्रायल कोर्ट नर्मदापुरम को एक वर्ष के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था। स्टेट टाइगर फोर्स ने वैज्ञानिक विवेचना करते हुए ताशी शेरपा की ब्रेन-मैपिंग और पॉलीग्राफी परीक्षण करवाया, जिससे उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण सबूत मिले। इसके अतिरिक्त साबर डेटा भी एकत्र कर न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किये गये।

देश का यह पहला मामला है, जिसमें बाघ शिकारियों, कुरियर, विचौलियों और तस्करों सहित 28 अपराधियों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सभी दोषी ठहराये गये।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्यप्रदेश को फंट रनर स्टेट का दर्जा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी क्रम में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में निजी उद्योग की भूमिका और सहभागिता को बढ़ाने के लिए भारत जर्मन सहयोग परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय कार्यशाला भोपाल के कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल में 3 जुलाई को सुबह दस बजे से आयोजित की गई है। कार्यशाला में मध्यप्रदेश के विभिन्न विभाग, जिलों के प्रतिनिधियों, नीति आयोग, जर्मनी की संस्था जीआइएड के प्रतिनिधियों से सतत विकास के लक्ष्यों और उनके स्थानीयकरण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मध्यप्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण में तेजी आई है और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्यप्रदेश को फंट रनर स्टेट का दर्जा मिला। प्रदेश में उत्पादन और जिम्मेदार पूर्ण उपभोग, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ

स्वच्छता, शहरीकरण, गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय काम हुआ है। मध्यप्रदेश के प्रयासों से 2.30 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करते हुए मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल करने के लिए आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत के प्रावधान के लिए जल जीवन मिशन में उल्लेखनीय काम हुआ है। मध्यप्रदेश देश के उन पहले राज्यों में से एक है जिसने भोपाल शहर के लिए स्वेच्छिक स्थानीय समीक्षा की और इंदौर विभाग, जिलों के प्रतिनिधियों, नीति आयोग, जर्मनी की संस्था जीआइएड के प्रतिनिधियों से सतत विकास के लक्ष्यों और उनके स्थानीयकरण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मध्यप्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण में तेजी आई है और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्यप्रदेश को फंट रनर स्टेट का दर्जा मिला। प्रदेश में उत्पादन और जिम्मेदार पूर्ण उपभोग, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ

कार्यशाला में जर्मन दूतावास और यूएनडीपी के प्रतिनिधि, भारत जर्मन सहयोग परियोजना की प्रमुख श्रीमती हेनरी पेईचर्ट, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री राजीव कुमार सेन और सतत विकास लक्षण के क्रियान्वयन से जुड़े विषय विशेषज्ञ, आर्थिक सलाहकार, कॉर्पोरेट भागीदारी से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

शहडोल सांसद ने अपनी बेटी का एडमिशन शासकीय विद्यालय में कराया



मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। शहडोल सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने अपनी बेटी गिरीश नंदिनी सिंह का एडमिशन अनुपपुर जिले के ग्राम राजेंद्र के शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय में कराया है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह के इस निर्णय की सराहना की। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस सकारात्मक संदेश से अन्य जन-प्रतिनिधियों एवं नागरिकों को प्रेरणा मिलेगी। जन-सामान्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर कर रहे एक-दूसरे को डेट!

नई दिल्ली,एजेंसी। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक वायरल हुआ वीडियो है। 8 जुलाई को लंदन में युवराज सिंह के कैसर फाउंडेशन के लिए एक चैरिटी डिनर पार्ट आयोजित की गई थी, जिसमें दुनियाभर के क्रिकेट दिग्गज जैसे ब्रायन लारा, केविन पीटरसन, विराट कोहली और भारतीय टीम के कोच और सभी खिलाड़ी मौजूद थे। इसी इवेंट में सारा तेंदुलकर भी नजर आईं। वो अपने पिता सचिन और मां अंजली के साथ पहुंचीं थी। वहीं शुभमन गिल भी भारतीय टीम के साथ

इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। इस पार्टी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसमें टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जैसे ही इवेंट वेन्यू में एंट्री करते हैं, लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं और फोटो व वीडियो बनाते हैं। इन्हीं में से एक शख्स नजर आती हैं सारा तेंदुलकर, जो खिलाड़ियों को अपने फोन के कैमरे में कैद कर रही थी, लेकिन गौर करने वाली बात ये रही कि जब तक सारा ने कैमरा ऑन किया, तब तक शुभमन गिल वहां से गुजर चुके थे। वीडियो से साफ है कि गिल खिलाड़ियों के थोड़ा आगे चल रहे थे

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरफ्तार

नई दिल्ली ,एजेंसी। तेलंगाना सीआईडी ने दावा किया है कि क्रिकेट बॉल, एयर कंडीशनर, खेल परिधान और प्लंबिंग के आरोप हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ए जगन मोहन राव पर लगे हैं। ए जगन मोहन राव ने एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सीजे श्रीनिवास राव और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कांते के साथ मिलीभगत करके कथित तौर पर धन का दुरुपयोग किया। तेलंगाना अपराध जांच विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कथित हेराफेरी कम से कम 2.32 करोड़ रुपये की थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कथित हेराफेरी 6 मामलों में हुई, जिसमें खानपान सेवाओं का आवर्टन और विद्युत सामग्री की खरीद शामिल है। सीआईडी का मामला 9 जून 2025 को

तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव डी गुरुबा रेड्डी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। एफआईआर के अनुसार, जगन मोहन राव ने एचसीए की टॉप परिषद के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कथित तौर पर 1.03 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। जगन मोहन राव ने ये दावा किया था कि उक्त राशि बीसीसीआई के घरेलू सत्र 2024-25 के लिए क्रिकेट गेंदों की खरीद पर खर्च की जा रही है। एफआईआर में लिखा है कि, इतनी बड़ी रकम में खरीदी गई गेंदों की संख्या सिर्फ 1340 थी। एफआईआर में लिखा है कि इस खरीद में राव ने निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन किया और स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा। इसी तरह नए एयर कंडीशनर पर कथित तौर पर 11.85 लाख रुपये खर्च किए गए बताए गए हैं।

फीफा रैंकिंग में भारत 133वें स्थान पर, नौ साल में सबसे खराब रैंकिंग

नई दिल्ली ,एजेंसी। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जून में मिली दो हार से गुरुवार को जारी फीफा रैंकिंग में छह पायदान की गिरावट से 133वें स्थान पर खिसक गई। भारत चार जून को एक अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में थाईलैंड (0-2) से हार गया और फिर एशियाई कप क्वालीफाईंग दौर के मैच में उसे निचली रैंकिंग वाली हांगकांग (0-1) से भी पराजय झेलनी पड़ी। इसके बाद मुख्य कोच मनोली मारकेज ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) से नाता तोड़ लिया। इससे पहले पिछली बार भारतीय टीम की सबसे खराब रैंकिंग दिसंबर 2016 में थी जब वह 135वें

स्थान पर थी। भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग फरवरी 1996 में 94 थी। भारतीय टीम के अभी 1113.22 रेटिंग अंक हैं जबकि पहले उसके 1132.03 अंक थे। वह 46 एशियाई देशों में 24वें स्थान पर है जिसमें जापान (17वीं रैंकिंग) सबसे आगे है।भारतीय पुरुष टीम के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हांगकांग के खिलाफ हार ने टीम की 2027 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करने की मुहिम को मुश्किल में डाल दिया है। मारकेज के मार्गदर्शन में टीम ने अपने पिछले आठ में से सिर्फ एक मैच में जीत दर्ज की और उसे यह जीत मार्च में मालदीव के खिलाफ मिली थी।

एशिया कप 2025 होगा रद्द ! भारत और श्रीलंका ने किया बड़ा ये फैसला

नई दिल्ली ,एजेंसी। सितंबर में होने वाले एशिया कप 2025 पर संकट के बादल और ज्यादा मंडराने लगे हैं। अब इस टूर्नामेंट के रद्द होने की संभावना जताई जा रही है। बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 24 जुलाई को ढाका में होने वाली एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। दरअसल, टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों बोर्ड ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब 6 देशों के इसटूर्नामेंट के शुरू होने में दो महीने से भी कम दिन बचे हैं। हालांकि,एसीसी ने पुष्टि की है कि बैठक योजना के अनुसार होगी, लेकिन भारत और श्रीलंका की अनुपस्थिति इस टूर्नामेंट के प्यूचर को खतरे में डाल रही है। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इससे पहले 24 जुलाई को ढाका में होने वाली एसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट के हिस्सा न लेने से इस टूर्नामेंट के होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीसीसीआई ने एसीसी की मीटिंग ढाका में होने पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड



के अध्यक्ष मोहसिन नकवी वर्तमान में एसीसी के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत के बांग्लादेश दौरे को

अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए मना लिया था। ये दौरान अगस्त में होने वाला था, लेकिन एसीसी ने अपनी बैठक ढाका में आयोजित कर दिया, जिससे बीसीसीआई खुश

नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के राजनीतिक हालात इस समय सही नहीं हैं। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार, एशिया कप की मेजबानी को लेकर बीसीसीआई की चुप्पी के कारण प्रायोजक और प्रसारणकर्ता असमंजस में हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हाइब्रिड मॉडल पर सहमत हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतसे किसी दूसरे देश में मैच खेलेगा। ये जानने के लिए कि क्या भारत अभी भी टूर्नामेंट की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? एसीसी ने बीसीसीआई से औपचारिक रूप से पूछताछ की है। वहीं बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने एसीसी को अपने अधिकारियों को ढाका भेजने से मना कर दिया है। एसीसी द्वारा ढाका में ये अहम बैठक आयोजित करना सही नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के राजनीतिक हालात इस समय ठीक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर एशिया कप स्थगित होता है तो बीसीसीआई एक दूसरी सीरीज आयोजित करने पर विचार कर रहा है। एशिया कप का आयोजन 5 सितंबर से यूई में होने की संभावना है।

अंपायर से भिड़ गए कप्तान शुभमन गिल, जमकर हुई बहस

नई दिल्ली ,एजेंसी। लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल को गुस्से में देखा जा सकता है। पहले सेशन में गिल के साथ ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अंपायर पर भड़कते दिख रहे हैं। इस दौरान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। दरअसल, इंग्लैंड की पारी के 91वें ओवर में हुई, जब भारत दूसरे दिन के पहले घंटे के खेल के दौरान बेन स्टोक्स, शतकवीर जो रूट और क्रिस वोक्स को आउट करने के बाद मैच पर हावी था। 91वें ओवर



की कुछ गेंदों के बाद जब दूसरी नई गेंद 10.4 ओवर पुरानी थी, गिल ने गेंद के आकार को लेकर शिकायत

संकेत मिले, क्योंकि चौथे अंपायर बॉल बॉक्स लेकर आया। अंपायरों ने एक गेंद चुनी और गिल तुरंत उससे नाखुश हो गए। उन्होंने अंपायर शरफुद्दौला से तीखी बहस की। गिल पीछे हटने को तैयार नहीं थे और लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन उन्हें अपनी फील्डिंग पोजीशन पर वापस जाने को कहा गया ताकि खेल फिर से शुरू हो सके। सिराज अंपायर के पास गए और गेंद को देखा, उसके बाद स्टंप माइक पर उन्हें ये कहते सुना गया, ये 10 ओवर पुरानी गेंद हैं? सचमुच?

इस खिलाड़ी ने 34 साल की उम्र में लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास

नई दिल्ली ,एजेंसी। आयरलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज पीटर मूर ने 34 साल की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 85 मैच खेले। बता दें कि, आयरलैंड के इस बड़े खिलाड़ी ने इस टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया था। उन्होंने आयरलैंड के लिए सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट ही खेला। वहीं, आयरलंड के पीटर

मूर ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच उसी देश के खिलाफ खेला, जिसके लिए उन्होंने डेब्यू किया था। जी हां इस बल्लेबाज ने दो देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला। 2 फरवरी 1991 को मूर का जन्म जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ था। पीटर मूर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू 26 नवंबर, 2014 को जिम्बाब्वे के लिए खेलेत हुए बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए ही 2016 में टेस्ट और टी20



में डेब्यू किया।

2019 में उन्हें जिम्बाब्वे का उपकप्तान भी नियुक्त किया गया, लेकिन इसके बाद उनके करियर में एक नया मोड़ आया। पीटर मूर ने

आयरिश पासपोर्ट मिलने के बाद आयरलैंड क्रिकेट टीम में जगह बना ली। उन्होंने ढाका में साल 2023 में 32 साल की उम्र में आयरलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया।

लॉर्ड्स में जो रूट ने जड़ा शतक, राहुल द्रविड़ का ये रिकॉर्ड तोड़ा



नई दिल्ली ,एजेंसी। लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वहीं इस दौरान इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने आखिरकार अपने फेवरेट वेन्यू में ये इंतजार खत्म कर दिया। ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में जो रूट ने टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में एक यादगार शतक जमा दिया। ये रूट के टेस्ट करियर का 37वां शतक है और इसके साथ ही वो

महान भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्टीव स्मिथ से आगे निकल गए। लॉर्ड्स में 10 जुलाई से शुरू हुए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बैटिंग के लिए उतरे रूट 99 रन पर नाबाद लौटे थे। ऐसे में हर किसी की नजरें इस पर थीं कि क्या वो दूसरे दिन अपना शतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। लेकिन रूट ने नर्वस नाईटीज की बाधा को पार किया और ये

मुकाम हासिल कर लिया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रूट ने दिन की पहली ही गेंद पर चौका जमाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर पहुंच गए। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड के लिए जो रूट को पहले सेशन में ही क्रीज पर उतरना पड़ा था। सिर्फ 44 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद रूट ने ऑली पोप के साथ मिलकर पारी को संभाला और टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। फिर उन्हें कप्तान बेन स्टोक्स का साथ मिला और दोनों ने दिन का खेल खत्म होने तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि, दूसरे दिन रूट का शतक होने के बाद वह अपना विकेट गंवा बैठे। रूट के नाम अब 37 शतक हो गए हैं। उन्होंने इस तरह पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा स्टार स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ दिया है। दोनों के नाम 36-36 शतक हैं। इस तरह सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस, रिकी पॉटिंग और कुमार संगकारा के बाद रूट सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं।

लॉर्ड्स में नीतीश कुमार रेड्डी का कमाल, सालों बाद ऐसा कमाल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने

नई दिल्ली ,एजेंसी। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जहां, पहले दिन लंच तक मेजबान टीम को दो विकेट झटके लग गए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैक क्रॉउली और बेन डकेट ने इंग्लैंड की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन जब लगा कि दोनों सैट हो गए तो नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके साथ ही नीतीश रेड्डी के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। नीतीश कुमार रेड्डी 2002 के बाद इस तरह अपने पहले ही ओवर में दो विकेट झटकने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। 2002 के बाद अब तक केवल दो भारतीय तेज गेंदबाजों ने पुरुष टेस्ट मैचों में पारी के अपने पहले ओवर में दो बार विकेट लेने का कारनामा किया हैं। इरफान पठान ने 2006 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ हेट्ट्रिक ली थी। आज नीतीश कुमार रेड्डी ऐसा करने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने



उतरी इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में बेन डकेट को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद रेड्डी ने एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए इसी ओवर की आखिर गेंद पर जैक क्रॉली को भी पंत के हाथों आउटकर भारत को एक ही ओर में दोहरी सफलता दिलाई।

बता दें कि, बेन स्टोक्स ने कोच ब्रैंडन मैकुलम के मार्गदर्शन में खेलते हुए घरेलू मैच में सिर्फ दूसरी बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेन डकेट और जैक क्रॉली की सलामी जोड़ी ने पहले घंटे में 13 ओवर में बिना किसी नुकसान के 39 रन बनाकर इंग्लैंड को सतर्क शुरुआत दिलाई। मैदान की ढलान के कारण भारतीय गेंदबाजों को गेंदबाजी करते समय अभ्यास होने में कुछ समय लगा।

खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई

अवैध रेत परिवहन करते 6 वाहन जप्त, लगाया 50,000 का जुर्माना



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर तथा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिला खनिज उड़नदस्ता दल एवं पुलिस विभाग ने 8 और 9 जुलाई 2025 को झगराखंड, तेन्दुदंड और भल्लौर क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई

करते हुए रेत एवं गिट्टी के अवैध परिवहन में लिप्त छह वाहनों को जप्त किया है। इस संयुक्त दल ने हसदेव एवं हसिया नदी क्षेत्र का सघन निरीक्षण कर झगराखंड क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर और 1 टिप्पर तथा भल्लौर क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर वाहन को अवैध परिवहन

में सलिप्त पाते हुए जप्त किया। जप्त वाहनों में से एक ट्रैक्टर वाहन को कलेक्टरेट परिसर में तथा शेष पांच वाहनों को झगराखंड थाने में सुरक्षार्थ रखा गया है। सभी छह वाहनों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957



की धारा 21 से 23 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम बिछियाटोला में शिशुपाल पनिका के नाम से स्वीकृत खनिज रेत अस्थायी भंडारण अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन,

परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के उपनियम 7(4) के तहत कार्रवाई करते हुए 50,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया, जिसे खनिज मद में जमा कराया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के दिशा-निर्देशों के

अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य में रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

मनेंद्रगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नई सौगात

चैनपुर में बनेगा जवाहर नवोदय विद्यालय, 11.8 हेक्टेयर भूमि का किया गया चिन्हांकन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मनेंद्रगढ़ अब स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। क्षेत्रवासियों के लिए एक और बड़ी सौगात के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। चैनपुर में इस विद्यालय के लिए 11.8 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है।



स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निरंतर प्रयासों से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव हो सकी है। उनके नेतृत्व में मनेंद्रगढ़ को पहले ही मेडिकल कॉलेज जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मिल चुकी है, और अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना से अब जिले के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

तालाब में डूबने से भाई-बहन समेत 4 बच्चों की मौत

इनमें 3 बच्चियां और एक लड़का, सभी की उम्र 5-8 साल, कपड़े-चप्पल देखकर चला पता

मीडिया ऑडीटर, जांजगीर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में शनिवार दोपहर तालाब में नहाने गए भाई-बहन समेत 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 3 लड़कियां और एक लड़का शामिल है। चारों बच्चे अलग-अलग तीन परिवार के थे। घटना बलौदा थाना क्षेत्र के भैंसतरा गांव की है।



शनिवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच चारों बच्चे स्कूल से लौटे। घर में बैंग रखकर तालाब की ओर चल दिए। तालाब उनके घरों से अधिक दूर नहीं था। यह गांव में रोजमर्रा की एक सामान्य बात थी। बच्चे गर्मी में तालाब में नहाते थे, लेकिन इस बार बड़ा हादसा हो गया।

परिजनों ने बताया कि कुछ समय बाद चारों के लिए भोजन नहीं लौटे, तो परिजन परेशान हुए। उनकी खोज में निकल पड़े। तालाब के किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पल पड़े देखे गए, जिससे अनहोनी का शक हुआ। ग्रामीणों ने पानी में तलाश शुरू की। कुछ ही देर में चारों को बाहर निकाला गया।

इसके बाद परिजन तुरंत सीएससी बलौदा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की सूचना मिलने पर बलौदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

भारत पेट्रोलियम की गैस पाइप लाइन परियोजना को मिली राहत

नगर पालिका का निर्णय को कलेक्टर ने किया निलंबित

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट द्वारा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी "सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन" परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एम.डी.पी.ई. माध्यम घनत्व पॉलीथिन पाइपलाइन डाय 32 इंच / 63 इंच / 90 इंच / 125 इंच के माध्यम से नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति 15 मार्च 2024 को दी गई थी, जिसमें कार्य पूर्ण करने की 6 माह की शर्त अधिरोपित की गई थी। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर अनुमति निरस्त मानी जानी थी, किंतु शर्तों के अनुसार भारत पेट्रोलियम द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

पत्र दिनांक 4 जुलाई 2025 का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि यह परियोजना न केवल मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले बल्कि आगे चलकर कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा एवं बलरामपुर तक विस्तारित होगी, जिससे इस परियोजना में वृहद जनहित निहित है। यह परियोजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय महत्व की योजना है, जिसे भारत पेट्रोलियम जैसा अर्धशासकीय लोक उपक्रम क्रियान्वित कर रहा है। यह भी स्पष्ट किया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा जारी मूल अनुमति में ही शर्त संख्या 14 के तहत अवधि विस्तार हेतु आवेदन देने का प्रावधान था, जिसकी पूर्ति बीपीसीएल द्वारा समय रहते कर दी गई थी। फिर भी, परिषद द्वारा उसका निराकरण बिना किसी कारण के अस्वीकार करना न केवल प्रशासनिक रूप से अनुचित बल्कि वृहद जनहित की अवहेलना भी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ का निर्णय "संकुचित दृष्टिकोण" और "कारण रहित प्रस्ताव" पर आधारित है, जो राष्ट्रीय हित एवं जनसाधारण की सुविधा के विपरीत है। इसलिए नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ की साधारण बैठक 12 जून 2025 के अतिरिक्त निर्णय क्रमांक 13(1) को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 323(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़-1 गैस टेरिटोरी, अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि परियोजना कार्य के दौरान लोक गैस स्प्रीकरण पर नगर पालिका ने अपने निर्णय पर स्थिर रहने का पत्र प्रस्तुत किया।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के

जिले में अब तक 354.4 मि.मी. वर्षा दर्ज

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में मानसून ने जोर पकड़ लिया है और लगातार हो रही बारिश से खेतों में हरियाली की उम्मीदें प्रबल हो गई हैं। भू-अभिलेख शाखा के अनुसार, तहसीलवार वर्षा की बात करें तो मनेंद्रगढ़ में 307.5 मि.मी., खड़गावां में 319.2 मि.मी., चिरमिरी में 345.2 मि.मी., केल्लहारी में 277.7 मि.मी., भरतपुर में 451.7 मि.मी. और कोटाडोल में 425.1 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 11 जुलाई 2025 तक जिले में कुल औसत

354.4 मि.मी. वर्षा भू-अभिलेख शाखा द्वारा दर्ज की गई है, जो शीघ्र फसलों की बोआई के लिए अनुकूल मानी जा रही है। भू-अभिलेख शाखा के अनुसार, तहसीलवार वर्षा की बात करें तो मनेंद्रगढ़ में 307.5 मि.मी., खड़गावां में 319.2 मि.मी., चिरमिरी में 345.2 मि.मी., केल्लहारी में 277.7 मि.मी., भरतपुर में 451.7 मि.मी. और कोटाडोल में 425.1 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है।

ग्राम अक्तवार में हैंडपंप मरम्मत और क्लोरीनेशन से ग्रामीणों को मिली स्वच्छ जल की सौगात



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम अक्तवार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा हैंडपंप मरम्मत एवं जल स्रोतों की शुद्धता हेतु क्लोरीनेशन का कार्य कर ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है। पिछले कुछ समय से ग्रामीणों द्वारा हैंडपंप से गंदा पानी निकलने की शिकायत की जा रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय टीम मौके पर पहुंची और तकनीकी रूप से हैंडपंप की मरम्मत की गई। इसके साथ ही जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन मिश्रण कर पेयजल को शुद्ध किया गया।

इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों को राहत मिली है और अब उन्हें स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो रही है। कार्य के दौरान स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग भी उत्कलनेश्वरी रहा, जिससे कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सका। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां आगे भी गांव-गांव में की जाएंगी ताकि हर व्यक्ति को शुद्ध जल सुलभ हो सके। ग्रामवासियों ने विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल न केवल उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगी, बल्कि जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी।